

मुकदमों का विवरण

एच. डी. सुंदरा और ओआरएस बनाम

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 247) 26 सितंबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश अपास्त करते हुए में न्यायसंगत ठहराया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 378-दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील-अभियुक्त और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच संपत्ति पर विवाद से संबंधित मामला-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर हमला किया-निचली विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, हालांकि अपराध के लिए दोषसिद्धि दंडनीय है। 304 भाग I और एस। 324/149 उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी.-सच्चाई:

आयोजित किया गया: साक्ष्यों की पुनः सराहना करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और यह इंगित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था-उच्च न्यायालय ने किसी भी कारण को दर्ज किए बिना और अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निभाई गई भूमिका के बारे में कोई निर्णय दर्ज किए बिना अभियुक्त को दोषी ठहराया-इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि मृत और घायल गवाहों को लगी चोटों के लेखक कौन थे-इस बारे में कोई निर्णय नहीं कि कैसे। 149 भारतीय दंड संहिता सी. आकर्षित हुआ-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, अपना कर्तव्य नहीं निभाया है-हालांकि, मामले को वापस नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि लगभग दो दशक पहले अपराध हुआ था-निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्ष और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन किया गया है-निचली विचारण न्यायालय गहन जांच के बाद गवाहों की गवाही को स्वीकार करने में असमर्थ थी-48

निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष संभावित निष्कर्ष थे-इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-एस. एस.304 भाग I और 324/149।[पारस 11-15]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** -धारा **378**-दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील-दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग।**378** - सामान्य सिद्धांत-उल्लिखित।[पैरा **7** और **8**]

बरी किए जाने के खिलाफ अपील-साक्ष्य की प्रशंसा:

आयोजित किया गया:कई मामलों में, बरी करने का आदेश पारित करने वाले विचारण न्यायाधीश के पास सभी भौतिक गवाहों की मौखिक गवाही दर्ज करने का अवसर होता है-अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लेते समय, उनका व्यवहार विचारण न्यायाधीश के दिमाग के पीछे रहता है-एक गवाह का व्यवहार अक्सर उसकी गवाही के वजन का संकेत देता है-बरी होने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखना पड़ता है।[पैरा 9]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सरकार द्वारा साक्ष्य का विधि -संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील No.247।

2004 के सी. आर. एल. ए. No.1807 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. बी. गुरुराज, श्रेयस कौशल, सुधाकरन, प्रकाश रंजन नायक, अनिमेष दुबे, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

निशांत पाटिल, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, महेंद्र पाल गुप्ता, मो. अपजल अंसारी, आयुष पी. शाह, विग्नेश आदित्य एस., शुभांशु पाधी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

एच. डी. सुंदरा और ओआरएस बनामकर्नाटक राज्य 50

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अभय एस. ओका, न्या .

1. यह अभियुक्तों द्वारा बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील है, जिसके द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा पारित उनके बरी होने के आदेश को पलट दिया गया था। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 304 की धारा 1 और धारा 324 के साथ धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें सात साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना दिया गया। 5, 000/-।

वास्तविक पहलू

2. हम मामले के कुछ तथ्यात्मक पहलुओं का उल्लेख कर सकते हैं। पीडब्लू-1 (जगदीशा) शिकायतकर्ता है। शिकायतकर्ता के परिवार के पास हेब्बले गाँव में संपत्ति थी। अपीलार्थी नं. 1 - अभियुक्त नं. 1-मरियप्पा पीडब्लू-1 के चाचा हैं, जिनके साथ पीडब्लू-1 के परिवार का पानी को लेकर विवाद चल रहा था। मंजूनाथ और शिवराम पीडब्लू-1 के भाई हैं, जो अफेंस के शिकार हैं। 29 अगस्त 1999 को, दोनों ने अदरक तोड़ने के लिए मजदूरों को शामिल करने के लिए हेब्बले गाँव में प्रवेश किया। पीडब्लू-1 ने उनका पीछा किया। गाँव के रास्ते में, उन्होंने पाया कि पीडब्लू-2 (सुंदरा) और पीडब्लू-6 (रवि) एक पुलिया पर बैठे थे। जब वह उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने गाँव से शोर-शराबा सुना, और इसलिए, वे गाँव में दौड़े और पाया कि अपीलकर्ता, जो पीडब्लू-1 के रिश्तेदार हैं, उनके पास डंडे, काठी और डंडे जैसे विभिन्न हथियार थे और वे मंजूनाथ और शिवराम पर हमला कर रहे थे। आरोप है कि आरोपी नं. 1-मरियप्पा ने एक क्लब का उपयोग करके शिवराम पर हमला किया। अभियुक्त नं. 8-पुट्टप्पा ने क्लब का उपयोग करके मंजूनाथ पर भी हमला किया। अभियुक्त नं. 7-राजप्पा ने शिवराम पर हमला करने के लिए हमले के हथियार के रूप में एक छड़ी का इस्तेमाल किया। अभियुक्त नं. 5-सोमशेखर ने चाकू से शिवराम पर वार किया। अभियुक्त नं. 6-कृष्णप्पा ने क्लब का उपयोग करके मंजूनाथ के सिर पर हमला किया। इसके अलावा, आरोपी नं. 3-चंद्रहास ने शिवराम की छाती पर पत्थर रखा। यहां तक कि आरोप नहीं लगाया। 4-राजकुमार ने एक पत्थर से शिवराम के पैर को कुचल दिया। हालांकि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-6 ने मृतक को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे मृतक को नहीं बचा सके। अभियुक्त नं. 3-चंद्रहास ने पीडब्लू-2 (सुंदरा) को पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया।

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक दरांती (काठी)। अभियुक्त नं. 1 ने एक क्लब के साथ पीडब्लू-1 पर हमला किया। अभियुक्त नं. 1 पीडब्लू-1 की माँ पर भी दाहिने हाथ से हमला किया।

3. विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। हालाँकि, आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

4. अभियुक्त नं.6 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी नं.1 - अपीलार्थी नं.1 और अभियुक्त नं.7 - अपीलार्थी नं.7 इस अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों के वकील ने 2023 की आई. ए. संख्या 71417-अतिरिक्त दस्तावेजों को दर्ज करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। अनुलग्नक ए-1 और ए-2 अपीलार्थी सं.1 और अपीलार्थी नं.7 क्रमशः। उक्त आवेदन की अनुज्ञात है और कारण शीर्षक को तदनुसार संशोधित किया गया है। कारण शीर्षक में औपचारिक संशोधन तदनुसार किया जाए। इन दोनों अपीलार्थियों के संबंध में अपील समाप्त हो गई है। अभियुक्त नं.2 - अपीलार्थी नं.2, अभियुक्त नं.3 - अपीलार्थी नं.3, अभियुक्त नं.4 - अपीलार्थी नं.4 और अभियुक्त नं.6 - अपीलार्थी नं.6 अब तक लगभग एक वर्ष और दो महीने की अवधि के लिए कारावास से गुजरे हैं। अभियुक्त नं.5 - अपीलार्थी नं.5-सोमशेखर पाँच साल और तीन महीने से जेल में हैं।

### प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर अपना दिमाग नहीं लगाया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कोई तथ्य दर्ज नहीं किया है कि एकमात्र संभव निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है। इस तरह के किसी भी आदेश को दर्ज किए बिना, उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलट दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय दर्ज नहीं किया गया है कि प्रत्येक अभियुक्त या कोई विशेष अभियुक्त दो मृतक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बना। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के लागू होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी हो रही है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि हालांकि एक गंभीर चोट आरोपी नं.1 - अपीलार्थी नं.1, अभियोजन पक्ष ने उक्त चोट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त चोट को देखते हुए, वास्तव में, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ. आई. आर. ') दर्ज की जानी चाहिए थी, और एक जांच की जानी चाहिए थी।

51

एच. डी. सुंदरा और ओआरएस बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.] 52

6. कर्नाटक राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निशांत पाटिल ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी बहुत कम घंटों की हो सकती है, जिसे समझाया गया है। इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य अपीलार्थियों के अपराध को एक उचित संदेह से परे साबित करते हैं। वास्तव में, यह एकमात्र निष्कर्ष होता जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर निकाला जा सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित निर्णय संतोषजनक नहीं है, तो यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के

साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री की फिर से सराहना करने के बाद, उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष की शुद्धता के बारे में अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट कर सकता है।

दलीलों पर विचार

7. इस अपील में, हमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.P.C') की धारा 378 के अंतर्गत बरी किए जाने के खिलाफ अपील का फैसला करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय की वैधता और वैधता पर विचार करने के लिए कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 378 के अंतर्गत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:- (क) अभियुक्त के बरी होने से निर्दोष होने की धारणा और मजबूत होती है।

(ख) अपीलीय विचारण न्यायालय, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की फिर से सराहना करने का हकदार है; (ग) अपीलीय विचारण न्यायालय, बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय, साक्ष्य की फिर से सराहना करने के बाद, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या विचारण विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था।

(घ) यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक और दृष्टिकोण भी संभव था; और

(ङ) अपीलीय न्यायालय बरी किए जाने के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर जो एकमात्र निष्कर्ष दर्ज किया जा सकता है वह यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

8. आम तौर पर, जब कोई अपीलीय न्यायालय अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य यह पता लगाना है कि जो निर्णय चुनौती के अंतर्गत है वह विधि और तथ्यों में सही है या गलत। अपीलीय न्यायालय आम तौर पर यह पता लगाता है कि चुनौती के अंतर्गत निर्णय कानूनी है या अवैध। लेकिन बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय केवल यह पता लगाने के लिए कि लिया गया दृष्टिकोण सही था या गलत, आक्षेपित निर्णय की जांच नहीं कर सकता है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, अपीलीय न्यायालय को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या निचली अदालत का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था। अपीलीय

न्यायालय बरी किए जाने के फैसले को केवल इस आधार पर पलट नहीं सकता कि साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, यह विचार है कि अभियुक्त का अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था। केवल इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करके बरी करने के आदेश को तब तक उलट नहीं किया जा सकता जब तक कि अपीलीय न्यायालय यह भी निष्कर्ष नहीं निकालता कि यह एकमात्र संभावित निष्कर्ष था। इस प्रकार, अपीलीय विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या किसी अभियुक्त को बरी करते समय विचारण विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर उचित रूप से लिया जा सकता है। यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि दूसरा दृष्टिकोण लिया जा सकता था।

9. इस मामले का एक और पहलू भी है। कई मामलों में, विद्वत विचारण न्यायाधीश जो अंततः बरी करने का आदेश पारित करता है, उसके पास सभी भौतिक गवाहों की मौखिक गवाही दर्ज करने का अवसर होता है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, विचारण विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाहों और उनके आचरण को बारीकी से देखने का अतिरिक्त लाभ होता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लेते समय, उनका आचरण विद्वान विचारण न्यायाधीश के दिमाग में रहता है। जैसा कि साक्ष्य के विधि पर सरकार की टिप्पणी में देखा गया है, एक गवाह का व्यवहार अक्सर उसकी गवाही के वजन का संकेत देता है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना होगा।

10. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, आक्षेपित निर्णय को ध्यान से देखने के बाद, हमें लगता है कि यह तय करने के लिए कि क्या उनकी गवाही पर विश्वास किया जा सकता है, चश्मदीद गवाहों की गवाही के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वास्तव में, साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई तथ्य दर्ज नहीं किए गए हैं। यह इंगित करने के लिए कोई तथ्य भी नहीं है कि उच्च विचारण न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 53

एच. डी. सुंदरा और ओआरएस बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.] 54

एक संभावित दृश्य था। किसी भी कारण को दर्ज किए बिना और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में कोई निर्णय दर्ज किए बिना, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त का अपराध स्थापित हो गया है। निर्णय इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डालता है कि मृतक और घायल गवाहों को लगी चोटों के लेखक कौन थे। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 कैसे आकर्षित होती है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

11. इस प्रकार, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि उच्च न्यायालय ने, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, अपना कर्तव्य नहीं निभाया है।

12. हालाँकि, हम रिमांड के आदेश का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि यह मामला लगभग साढ़े तेइस साल पहले हुआ है। हमने पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-3, पी. डब्ल्यू.-6 और पी. डब्ल्यू.-7 जैसे चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और विचारण न्यायालय के आदेशों का अध्ययन किया है। हम मानते हैं कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के बयानों का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है। घटना 9 की थी:00 पी. एम विचारण न्यायालय ने नोट किया कि 11 बजे:40 घटना के दिन शाम को अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा पीडब्लू-1 की जांच की गई थी। इसके तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह 1 पर पंजीकृत किया गया था:30 अगली तारीख को ए. एम. विचारण न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी नं. 11 'उनके अंगूठे पर पट्टी बंधी हुई थी। इस गंभीर चोट के लिए अपीलार्थी सं. 11 - अभियुक्त नं. 1, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

13. विचारण न्यायालय ने पाया कि चोट के कारण की जांच करने में विफलता आरोपी नं. 11 अभियोजन पक्ष के मामले में एक गंभीर कमी है। तथ्यों पर, विचारण विचारण न्यायालय द्वारा आगे यह नोट किया जाता है कि पूर्व शिकायत के आधार पर अभियुक्त नं. 1 - अपीलार्थी नं. 1 पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-12 द्वारा हमला करने का आरोप लगाते हुए, उन सभी को सक्षम न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई।

14. अभियुक्त और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। चश्मदीद गवाहों की गवाही की गहन जांच के बाद, दर्ज किए गए कारणों के कारण, विचारण न्यायालय उनकी गवाही को स्वीकार करने में असमर्थ रही। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और विचारण विचारण न्यायालय के साक्ष्यों की जांच करने के बाद, हमें यह मानना चाहिए कि विचारण विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष संभावित निष्कर्ष थे जो अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज किए जा सकते थे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

निर्णय 1 निर्णय 5 निर्णय .निर्णय निर्णय इनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय िनिर्णय एनिर्णय ,निर्णय निर्णय अनिर्णय पनिर्णय ीनिर्णय लनिर्णय निर्णय सनिर्णय फनिर्णय लनिर्णय निर्णय हनिर्णय ोनिर्णय निर्णय जनिर्णय ानिर्णय तनिर्णय ीनिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय हनिर्णय मनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 1 निर्णय निर्णय सनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय ंनिर्णय बनिर्णय रनिर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 0 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय आक्षेपित निर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय दनिर्णय रनिर्णय कनिर्णय िनिर्णय ननिर्णय

ानिर्णय रनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय निर्णय दनिर्णय ेनिर्णय तनिर्णय ेनिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ंनिर्णय ।निर्णय हम निर्देश देते हैं कि जब तक अपीलकर्ताओं को किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

## 16. तदनुसार अपील की अनुज्ञात जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन